दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

महिलाओं के प्रति साजिद का रवैया हमेशा असभ्य.... P-8

वर्ष : 14 अंक : 5 गाजियाबाद, अक्टूबर, 2018 मूल्य : 4 रूपया पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

केवाईसी में आधार नहीं होने पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं

सत्येन्द्र सिंह मुख्य संपादक एवं मनोज यादव क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

केवाईसी अपडेट होने पर कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी इसका लाभ होगा।

-मनोज यादव

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

18 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को आधार पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण अग्रिम आदेशों तक कम्पनियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। जिससे कम्पनी मालिकों को काफी राहत मिल गयी है तथा अब वे उन कर्मचारियों का के वाई सी अपडेट करवा सकेंगे जिनका नाम या जन्मतिथि या पिता का नाम मैच नहीं कर रहा था या गलत था इसके लिए उनको पहले आधार या बैंक या पैन कार्ड में उक्त त्रुटि को सही करवाना होगा तभी उनकी के वाई सी अप्डेट हो पाएगी क्योंकि तीनो सरकारी दस्तावेजों (पैन, आधार एवं बैंक अकाउंट) में नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि मिलनी चाहिए तभी कम्प्यूटर उसे ऑनलाइन स्वीकार करेगा।

अब नियोक्ताओ के साथ कर्मचारियों को भी अपना डेटा सही करवाने का पर्याप्त समय मिल गया है जिसका लाभ उठाकर वे लाभान्वित हो सकते हैं। इस सम्बंध में जब देहरादून के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज यादव से बातचीत की गयी तो उन्होंने कहा की हमारे क्षेत्र में काफी तेजी से इस दिशा में कार्य हो रहा है तथा डेटा अप्डेट रहने से कर्मचारियों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी लाभ होगा तथा पी एफ निकासी, या ट्रैन्सफर में सुविधा होगी।

विभाग इसी दिशा में निरन्तर प्रयासरत है की हम जल्दी ही पूर्ण रूप से पपेरलेस हो जाएँगे। एवं घर बैठे ही सारे कार्य सम्भव होंगे अब विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कारखाना लाइसेन्स के नवीनीकरण में विभाग का सॉफ्टवेयर फेल

❑ हार्ड कापी विभाग में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

-अनुराग श्रीवास्तव

निदेशक कारखाना उ.प्र

❑ कारखाना मालिकों से समय पर नवीनीकरण कराने का अनुरोध

-ओपी भारती

उपनिदेशक कारखाना

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

श्रम विभाग का सॉफ्टवेयर सर्वर की समस्या बताकर अक्सर काम नहीं कर रहा है पूरे पूरे दिन लोग चालान जमा करने एवं पेपर अपलोड करने के लिए इंतजार करते है लेकिन नहीं कर पा रहे है अब जबकि अंतिम तिथि निकट है एवं विभाग का कोई भी अधिकारी इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है ऐसे में नियोक्ता कहाँ जाएगा जबकि उसके ऊपर पूरा दबाव है की उसे 31 अक्टूबर के पहले चालान जमा करना है एवं न जमा करने पर 25% पेनल्टी का प्रावधान है। उपनिदेशक कारखाना ओ पी भारती ने सभी कारखाना मालिकों से समय पर नवीनीकरण करवाने का अनुरोध किया है ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। दूसरी समस्या यह है की जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं वे विभाग में अक्सर नहीं दिखाई देते है ऐसे में विभाग के अधिकारी उसे रिजेक्ट कर देते हैं एवं फिर से अपलोड करने को कहते हैं। इस प्रक्रिया में कारखाना मालिक ही पिस रहा है। जब लखनऊ एवं कानपुर में सॉफ्टवेयर कम्पनी वालों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वे बात करने से मना कर देते हैं तथा कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा है। इस कम्पनी का शुरू से ही अड़ियल रवैया रहा है जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताते हैं कि कम्पनी को ठेका पिछली सरकार के श्रम मंत्री ने दिया था एवं ये उनके रिश्तेदार भी हैं लेकिन इस सरकार में भी इनके ऊपर मेहरबानी समझ से परे है। जो कम्पनी 50 हजार का भी कार्य नहीं कर सकती है उसे लाखों का ठेका क्यों दिया गया है यह सोचनीय है। बहुत सी कम्पनियों ने ऑनलाइन फीस जमा कर दी है लेकिन पैसा कहाँ गया विभाग यह बताने में अक्षम है तथा कम्पनियों को दुबारा फीस जमा करनी पड़ रही है जबकि पुराना जमा किया पैसा कहाँ गया? उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गयी? कोई भी कुछ भी मुँह खोलने को तैयार नहीं है. इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज रोहित श्रीवास्तव कानपुर से उनके मोबाइल न 8081710687 पर बात करने की कोशिश की गयी लेकिन फोन लगता ही नहीं है. लखनऊ में फोन नं. 0522-4090503 पर किन्हीं दिवांग ने काल उठाई फिर उसे किन्हीं सायरा को ट्रान्सफर करी लेकिन वे भी सही जवाब देने के बजाय गोलगोल घुमाती रहीं फिर बोलीं की आप विभाग से मालूम करिए हम लोग प्राइवेट है हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है.

ईमानदार टैक्सपेयर्स को VIP बनाएगी सरकार, फ्री में देगी ये सुविधाएं

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

अगर आप अपना टैक्स ईमानदारी से भरते हैं, तो आप सरकार के मेहमान बन सकते हैं. सिर्फ मेहमान ही नहीं, बल्कि सरकार आपको कई अन्य सुविधाएं भी दी देगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया है, जो इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगी. सरकार के इस कदम का उद्देश्य टैक्सपेयर और सरकार के बीच विश्वास बढ़ाना है. सरकार ने कालाधन निकालने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. इसमें बेनामी कानून बनाया गया. अब सरकार को लगता है कि ईमानदार टैक्सपेयर्स को ईनाम देना चाहिए. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे. CBDT की कमेटी रिवॉर्ड प्रोग्राम पर काम करेगी. इसके तहत ज्यादा टैक्स भरना चुनने की शर्त नहीं होगी. समय पर टैक्स भरने वाले, जिन पर पेनल्टी नहीं लगी है और छापा नहीं पड़ा है ऐसे लोगों को चुना जाएगा. इस तरह से जापान, फिलीपिंस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में टैक्स भरने वालों का सम्मान किया जाता है. जापान में इस तरह के टैक्सपेयर का वहां के राजा के साथ फोटो खिंचवाया जाता है. दक्षिण कोरिया में ईमानदार टैक्सपेयर्स को एयरपोर्ट पर VIP कमरे और फ्री पार्किंग की सुविधा मिलती है. रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत आपको राज्य के गवर्नर के साथ चाय पीने का मौका मिलेगा. यही नहीं, आपको एयरपोर्ट पर प्रायोरिटी चेक की सुविधा मिलेगी. इससे आपका समय बचेगा. इसके अलावा टोल प्लाजा पर ईमानदार टैक्सपेयर्स की खातिर एक अलग टोल लेन लगी होगी. जहां से गुजर कर आप अपना समय बचा सकते हैं. इसके अलावा आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगी. आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, तो आापको दूसरों के मुकाबले पहले पासपोर्ट मिलेगा. इस इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत मिलने वाली सुविधाओं में से ये कुछ हैं. यह लिस्ट लंबी हो सकती है. रिपोर्ट की मानें तो मॉडल टैक्सपेयर्स की जो परिभाषा तय की जाएगी, वह उसने कितनी रकम टैक्स में भरी, इससे नहीं होगी. बल्कि आप हमेशा टैक्स टाइम पर भरते हैं या नहीं. आप पर जुमार्ना तो नहीं लगा है. आपके खिलाफ सर्च और सर्वे की कार्रवाई तो नहीं की गई है. इन सब चीजों की जांच करने के बाद ही आपको फायदा दिया जाएगा.

अफसर नहीं चाहते निगम की आर्थिक स्थिति में हो सुधार

❑ सदन की बैठक में अधिकारियों को घेरने की तैयारी

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

गाजियाबाद। नगर निगम के अधिकारी नहीं चाहते कि निगम की आर्थिक हालात में सुधार हो। जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि निगम सीमांगर्त दिशा सूचक लगाते हुए बीओटी के आधार पर विज्ञापन लगाने के कारोबार में निजी फर्म द्वारा ढाई लाख रूपए सालाना के प्रीमियम के स्थान पर साढे चार करोड रूपए प्रीमियम के आधार पर ठेका हासिल करने का प्रस्ताव आने के दो माह बाद भी निगम के अधिकारी किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाए है।ये स्थिति उस वक्त है जब बीओटी,यूनीपोल तथा पार्किंग के खेल को लेकर लगातार गैर भाजपायी और सत्ताधारी पार्षद लगातार निगम कार्यकारिणी और सदन की बैठक के दौरान मुददे को लेकर अधिकारियों को कटघरे में खडा कर रहे है। माना जा रहा है कि ब्रहस्पतिवार को होने वाली निगम के सदन की बैठक के दौरान इन्हीं तमाम मुददों को लेकर फिर हंगामा हो सकता है। बीजेपी के पार्षद एवं जीडीए बोर्ड के सदस्य सचिन डागर ने भी संकेत दिए कि अधिकारियों की मनमानी को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। श्री डागर ने संकेत दिए कि सदन की बैठक के दौरान कई मुददों को लेकर अधिकारियों को घेरने का काम किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी से पार्षद दल के नेता आसिफ खान ने भी धरने का एलान किया है। निगम के सूत्रों से पता चला कि शास्त्री नगर के नीरज गुप्ता ने 6 जुलाई 2018 में नगर आयुक्त के सामने लिखित में लेटर दिया था। लेटर के माध्यम से कहा गया था कि निगम सीमांर्गत दिशा सूचक लगाकर विज्ञापन करने का कार्य बीओटी के आधार पर मैसर्स गेट मोर फर्म को दिया गया था। निगम के अनुबंध अनुसार ठेके की पर्यवेक्षा अवधि दो साल तय की गई थीं जो कि दिनांक 3 जनवरी 2018 को समाप्त हो गई थीं। पर्यवेक्षा अवधि के बाद तीन साल कार्य अवधि निश्चित की गई थीं। फर्म द्वारा पर्यपवेक्षा अवधि के दौरान भारी अनियमितताएं क गई थीं। निगम द्वारा फर्म के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे तथा फर्म के खिलाफ रिकवरी की मांग की गई थीं। जो आज भी फर्म द्वारा जमा नहीं करायी गई तथा आज भी फर्म द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी के द्दष्टिगत निगम द्वारा फर्म को कार्यावधि का नवीनीकरण नहीं किया गया है। फर्म द्वारा अभी विज्ञापन लगाकर जो कार्य किया जा रहा है वह पूरी तरह से अवैध है। इसमें भी फर्म को ठेका केवल ढाई लाख रूपए सालाना के प्रीमियम पर आवंटित किया गया था,जिससे निगम को हर साल करोडों रूपए का नुकसान हो रहा है जबकि वह उपरोक्त कार्य को चार करोड बीस लाख रूपए के प्रीमियम पर लेने के लिए इच्छुक है। इसके लिए प्रार्थी शपथ पत्र और अग्रिम धनराशि का डीडी निगम कोष में जमा कराने के लिए भी तैयार है। हैरत का पहलू ये है कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भी निगम प्रशासन किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाया है। समाजवादी पार्टी से पार्षद दल के नेता आसिफ खान ने कहा कि पूरे शहर भर में बीओटी,यूनीपोल और अवैध पार्किंग का खेल निगम अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है।

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8374.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

दिल्ली, यूपी समेत छह राज्यों में अब पेट्रोल-डीजल और शराब पर लगेगा एक समान टैक्स

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

चंडीगढ़। पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित चंडीगढ़ ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने पर मंगलवार को सहमति जताई है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इनके अलावा ये राज्य शराब, वाहनों के पंजीयन तथा परिवहन परमिट के मामले में भी एक समान दर रखने पर सहमत हुए हैं. पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर यहां एक बैठक में चर्चा की. बयान में कहा गया, बैठक के दौरान पेट्रोल एवं डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरें समान रखने पर सहमति बनी.

राज्यों ने यह भी निर्णय लिया कि इसके संबंध में एक उप-समिति गठित की जाएगी जो अगले 15 दिनों में दरें एक समान रखने को लकर सुझाव देगी. बैठक में यह भी निष्कर्ष निकला कि एक समान दरों से व्यापार के हेर-फेर पर रोक लगेगा. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बैठक में तय किया गया कि पेट्रोल, डीजल पर वैट दरों में समानता लाने के प्रयास किये जाने चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके. पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां पेट्रोल पर पर सबसे ऊंची दर से वैट लगता है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बैठक के बाद कहा, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसके साथ-साथ कालाबाजारी पर रोक लगेगी.

कमिश्नर की पहल पर डिजिटल डायरी शुरू

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

मेरठ। कमिश्नर अनीता सी मेश्राम की पहल पर मंडल स्तर पर 25 विभागों द्वारा संचालित 120 से अधिक लाभार्थीपरक योजनाओं का संग्रहण कर डिजिटल डायरी तैयार की गई है। इसे मेरठ मंडल की वेबसाइट http://meerutdivision.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। मंडल का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। डिजिटल डायरी खोलने के लिये meerutdivision.nic.in पर उपलब्ध लिंक Beneficiary Schemes/Digital Diary करने पर समस्त योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008
A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS &
PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT
Social & Technical Audit

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

☐ Payroll
☐ TDS
☐ ESI Act
☐ EPF Act
☐ Minimum Wages Act
☐ Bonus Act
☐ Payment of Gratuity Act
☐ Standing Order
☐ Workmen Health & Safety Policy
☐ First Aid Training & Certificates
☐ Factory Plan & Site Plan
☐ Factory Act-1948
☐ Shop & Establishment Act
☐ Social & Technical Audit

Our Website : www.legalipl.com, CMD - 9818697406 / 9818036460

H.O. : BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad
U.P.-201002. INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794
Mobile : 9818697406

B.O. : The Ithum IT Park, Suite
#007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida,
201301-U.P. India

E-mail ID : - legalipl243@gmail.com

यूपी में पांच हजार कंपनियां डिफाल्टर

यहां कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी

490 कंपनियां नोएडा की घोषित की गईं डिफाल्टर

300 कंपनियों पर लखनऊ में दर्ज होगा मुकदमा

400 कंपनियां कानपुर की आई कार्रवाई के दायरे में

267 मेरठ की कंपनियों पर की जा जाएगी कार्रवाई

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

कानपुर। पीएफ खाताधारकों के केवाईसी लिंक सही कराने वाली कंपनियों पर ईपीएफओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में पांच हजार कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल, इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के पीएफ खातों में आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर नहीं दर्ज किए जबकि उन्हें नोटिस के जरिये सितंबर में ही अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई थी। अब ईपीएफओ इनके खिलाफ क्षेत्रवार सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले पीएफ वाले पीएफ खाते कानपुर, नोएडा, मेरठ और लखनऊ की कंपनियों के मिले हैं। इन शहरों की कंपनियों ने अंशधारकों के केवाईसी लिंक करने का काम ही नहीं किया है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त वीवीबी सिंह ने डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर सीजेएम कोर्ट में डेढ़ दर्जन कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसमें चार हजार जुर्माना और एक साल की सजा का प्रावधान है।

मोदी सरकार लाएगी हवाई माल परिवहन

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्दी ही हवाई माल परिवहन नीति लाएगी और घरेलू विमानन क्षेत्र की सतत वृद्धि के लिये दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है. भारत का विमानन बाजार तीव्र वृद्धि करने वाले बाजारों में से एक है और करीब चार साल से दहाई अंक में वृद्धि दर्ज कर रही है. नागर विमानन मंत्री ने सुरक्षा, सुविधा और किफायत पर जोर देते हुये कहा कि 2035 के लिये विमानन दृष्टिकोण पत्र सभी मुद्दों का समाधान करेगा ताकि हम भारत में हर समय हवाई यात्रा क्षेत्र में सतत वृद्धि हासिल करें. मंत्रालय नागर विमानन क्षेत्र के लिये दृष्टिकोण पत्र 2035 दस्तावेज तैयार कर रहा है. प्रभु ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा पर सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, हम जल्दी ही हवाई माल परिवहन नीति लाएंगे. नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सुरक्षा समाधान के लिये एकीकृत कमांड, प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत प्रभाव के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा, हम संभवतः 15 साल में यात्री ड्रोन समेत सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने जा रहे हैं.

नियोक्ता के ध्यानार्थ

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

उन सभी स्थापनाओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आते हैं तथा जो अपने कर्मचारियों का 15,000/- रूपये की वैधानिक सीमा से अधिक पर पेंशन अंशदान जमा करवा रहे हैं।

यह एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 11(3) के नियम, जोकि उच्च दर पर पेंशन अंशदान की अनुमति देता था, को दिनांक 01/09/2014 से हटा दिया गया है। ऐसे नियोक्ता, जो अभी भी 15,000/- रूपये प्रतिमाह से ज्यादा वेतन पर अंशदान दे रहे हैं, वे प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।

अतः एतद्वारा अनुरोध है कि इस विसंगति को तत्काल ठीक करें तथा प्रत्येक कर्मचारी के पेंशन खाते में 15,000/- रूपये की वैधानिक सीमा तक ही पेंशन अंशदान जमा करें। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह भी ध्यान दिया जाए कि दिनांक 01/09/2014 से वैधानिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर जमा किए गए पेंशन अंशदान पर, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 11(4) के तहत, कोई पेंशन लाभ स्वीकार्य नहीं है।

-हस्त-
(एस.पी.सिंह)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II

#MeToo पर एमजे अकबर के खिलाफ खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही कांग्रेस?

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

देश भर में #MeToo कैंपेन के तहत यौन शोषण की शिकायतें सामने आ रही हैं. बॉलीवुड की जानी-मानी शख्सियतों के बाद इसमें मोदी सरकार में मंत्री एमजे अकबर का नाम भी शामिल हो गया है. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ लगभग 10 पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. इसके बाद उनपर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। लेकिन, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस मामले के खिलाफ अभी खुलकर सामने नहीं आई है.

बॉलीवुड #MeToo की गिरफ्त में, लेकिन बोल्ड भोजपुरी सिनेमा में खामोशी

दरअसल, यौन शोषण के खुलासे में फंसे एमजे अकबर पर अपनी पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मोर्चा खोल दिया है. लेकिन, अभी तक न तो कांग्रेस और न ही पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में कोई बयान आया है. गुरुवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से #MeToo आरोपों से घिरे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के बारे में सवाल पूछा गया, तो वो इसका जवाब देने से बचते रहे.

#MeToo: कांग्रेस ने की मांग- यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जवाब या फिर इस्तीफा दें अकबर

हालांकि, राहुल ने कहा कि #MeToo गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है. इस पर हम अलग से बात करेंगे. हमारी पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस मोदी सरकार को जनता से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर घेरती है, वह पार्टी यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसे चुप्पी क्यों साधी हुई है?

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो, पार्टी अभी राफेल डील पर ही फोकस करना चाहती है. ऐसे में राहुल गांधी का #MeToo या एमजे अकबर पर कुछ बोलना पार्टी के बिल्कुल खिलाफ जाता.

#Metoo: यौन उत्पीड़न के आरोप पर गायक रघु दीक्षित ने कहा- फिर माफी मांग लूंगा

हालांकि, कांग्रेस ने #MeToo कैंपेन पर मोदी सरकार पर कुछ हमले किए हैं, लेकिन ये हमले इतने हल्के थे कि इनकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी. राहुल गांधी ने #MeToo कैंपेन के समर्थन में ट्वीट किया है और उन्होंने यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग भी की. मोदी सरकार के जिस मंत्री पर यौन शोषण के 10 शिकायतें हो, उनके खिलाफ कांग्रेस को खुल कर सामने आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस अगर डिफेंसिव मोड में नहीं है, तो ऑफेंसिव मोड में भी नहीं है. क्योंकि, एमजे अकबर को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को आसानी से टारगेट कर सकती है. लेकिन, ऐसा नहीं हो रहा. विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर रविवार को नाइजीरिया दौरे से भारत लौट आये हैं. सूत्रों के मुताबिक, अपना नाम साफ न होने तक अकबर बीजेपी से भी इस्तीफा दे सकते हैं.

बता दें कि महिलाओं पर यौन शोषण के खिलाफ शुरू हुए #MeToo कैंपेन के तहत सामने आ रहे मामलों की जन सुनवाई के लिए कमिटी गठित कर दी गई है. महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों की चार सदस्यीय कमिटी इन सभी मामलों की सुनवाई करेगी.

श्रमिकों की समस्याओं को लेकर डीएम कैंप कार्यालय पर बैठक

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नोएडा। श्रमिकों की समस्याओं को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार शाम जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी बीएन सिंह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण अभी अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाए। बैठक में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा आगामी 16 अक्टूबर से प्रस्तातिव हड़ताल को लेकर भी जिला प्रशासन एवं ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के बीच गहनता के साथ विचार विमर्श किया गया। जिसमें जिलाधिकारी ने ट्रेड यूनियनों की जिला स्तर की समस्त समस्याओं का निस्तारण उप श्रम आयुक्त को तत्काल प्रभाव से करने का निर्देश दिया है। जो शासन स्तर की समस्या है उनके संबंध में तत्परता से शासन को लिखा जाए। इस पर सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने सहमति जताते हुए आगामी 16 अक्टूबर को प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया। जिलाधिकारी ने श्रम विभाग अफसरों को निर्देश दिया है कि श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण करने के उद्देश्य से बिल्डर एवं अन्य व्यापारियों तथा ट्रेड यूनियन के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक माह समीक्षा करते हुए श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के साथ करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर सुधा सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ललित ठुकराल के अथक प्रयास से 16 अक्टूबर को होने वाली ट्रेड यूनियन की हड़ताल रद्द

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नोएडा। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा, गौतमबुद्ध नगर ने 16 अक्टूबर को होने वाली एक दिवसीय हड़ताल रद्द कर दी है। सेक्टर-27 में कैंप ऑफिस पर डीएम बीएन सिंह के साथ नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्रिस्टल के चेयरमैन ललित ठुकराल की बैठक हुई। इसमें डीएम ने मोर्चा की मांगें शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद मोर्चा ने हड़ताल रद्द करने का फैसला लिया। ललित ठुकराल ने जिला मैजिस्ट्रेट, डीएलसी, जीएम-डीआईसी, सिटी मैजिस्ट्रेट, एसएसपी, सीओ और संयुक्त राष्ट्र यूनियन मोर्चा के संघ नेताओं के साथ बैठक कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि राहुल मिरा डिजाइन सेक्टर-7 और मैसर्स डी ज्वैल ऑफ नोएडा, सेक्टर-75 के मालिकों से बात कर कंपनी से निकाले गए कामगारों को रखने और उनका भुगतान करने के संबंध में बात हुई। हड़ताल से उद्योग को बहुत नुकसान होगा। राजस्व में भी कमी आएगी। यूनियन नेताओं को समझाने के बाद प्रस्तावित हड़ताल रद्द कर दी गई।

WRAP & "LA
BOUR" ADVISORS ASSOCI
Semina
AL & T
CE'S
LAW
rd July 20
C. Mathu
TOR-18, N
tendra Si
State Presider

ज़िलाधिकारी बीएन सिंह, उपश्रमायुक्त पी के सिंह एवं श्रमिकों के मध्य नॉएडा एक्सपोर्ट क्लस्टर चेयरमैन ललित ठुकराल ने मध्यस्थता करते हुए आगामी 16 अक्टूबर को होने जा रही हड़ताल को सफलता पूर्वक समाप्त करवाया। इस हड़ताल को समाप्त करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे मध्यस्थता करवाने में जिस तरह सफल हुए हैं उसी तरह एक अत्यन्त सफल उद्यमी भी हैं।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, अक्टूबर, 2018

सम्पादकीय

पटाखों का दायरा

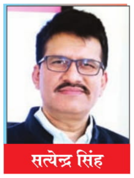

सत्येन्द्र सिंह

दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर खुशियों का इजहार करने के लिए बेहतर खानपान और रोशनी की सजावट से पैदा जगमग के अलावा कानफोडू पटाखों का सहारा लोगों को कुछ देर की खुशी तो दे सकता है, लेकिन उसका असर व्यापक होता है। पटाखों की आवाज और धुएं के पर्यावरण सहित लोगों की सेहत पर पड़ने वाले घातक असर के मद्देनजर इनसे बचने की सलाह लंबे समय से दी जाती रही है। ज्यादातर लोग इनसे होने वाले नुकसानों को समझते भी हैं, मगर इनसे दूर रहने की कोशिश नहीं करते। हालांकि पर्यावरणविदों से लेकर कई जागरूक नागरिकों ने इस मसले पर लोगों को समझाने से लेकर पटाखों पर रोक लगाने के लिए अदालतों तक का सहारा लिया है, लेकिन इन पर पूरी तरह रोक लगाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। पिछले साल शीर्ष अदालत ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन व्यवहार में उसका कोई खास फर्क नहीं नजर आया। अब इस साल सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली और दूसरे त्योहारों के अवसर पर कुछ शर्तों के साथ पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। इसमें सबसे अहम शर्त यह है कि रात में आठ बजे से लेकर दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा, अदालत के निर्देश के मुताबिक सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कारोबारी पटाखे बेच पाएंगे, जबकि ऑनलाइन व्यवसाय करने वाली वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। जाहिर है, प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ-साथ लोगों की सेहत के मद्देजनर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की खुशियों का भी ध्यान रखा है। अगर लोगों को अदालत के इस फैसले में छिपे संदेशों को समझना जरूरी लगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा सबको मिलेगा। पिछले साल अदालत ने पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई थी, उसके बावजूद पटाखों के शोर और धुएं में कोई कमी नहीं आई। यह किसी से छिपा नहीं है कि दिवाली के मौके पर लोग आमतौर पर नौ-दस बजे के बाद ही पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं और यह सिलसिला देर तक चलता रहता है। इस बार यह देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रात आठ से दस बजे तक की समय-सीमा का पालन अलग-अलग इलाकों के थाना प्रभारी कैसे सुनिश्चित करा पाते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पटाखे तैयार करने और खुशी मनाने के लिए उनका उपयोग करने की सलाह भी दी जाती रही है। लेकिन आस्था और त्योहार के नाम पर आमतौर पर इस तरह की सलाहों का ध्यान रखना लोग जरूरी नहीं समझते। दरअसल, दिवाली आने के साथ ही शायद बहुत कम लोगों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी लगता है कि खुशी जाहिर करने का अकेला विकल्प पटाखे जलाना नहीं है। खासतौर पर दिवाली का उत्सव मनाने के नाम पर जितनी बड़ी तादाद में पटाखे जलाए जाते रहे हैं, उसके बिना भी बराबर की खुशी हासिल की जा सकती है। लेकिन यह अमूमन हर साल की विडंबना रही है कि लोग पटाखों के धुएं और आवाज से परेशान और गंभीर रूप से बीमार भी होते हैं और इनके बिना उनकी दिवाली पूरी भी नहीं होती। इस दोहरी स्थिति में जीने का ही नतीजा यह होता है कि इस त्योहार की चकाचौंध के गुजर जाने के बाद पटाखों का धुआं और शोर अपने पीछे कई तरह की बीमारियां और पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक नुकसान छोड़ जाता है।

राममंदिर के लिए संसद में प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को 'हिन्दुत्व' पर घेरने की तैयारी

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की आहट के बीच एक बार फिर अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण का शोर सुनाई पड़ने लगा है। अबकी बार की खासियत यह है कि बीजेपी की मोदी-योगी सरकारें तो नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा वाले साधू-संत और हिन्दूवादी संगठन मंदिर निर्माण की तारीख भी बता रहे हैं। संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की मांग के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहें, 'बेवजह समाज के धैर्य की परीक्षा लेना किसी के हित में नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिये कानून लाए सरकार।' तो, समझा जा सकता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर कहीं न कहीं खिचड़ी पक जरूर रही है। साधू-संत तो बाकायदा यहां तक कह रहे हैं कि 06 दिसंबर 2018 से अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो जायेगा। खास बात यह है कि कई मुस्लिम संगठन भी अब मंदिर निर्माण के पक्ष में बोलने लगे हैं। खुद को बाबर का वंशज बताने वाले भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर निर्माण हुआ तो वह सोने की ईंट देंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद से ही मोदी सरकार के ऊपर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का चौतरफा दबाव बन रहा है। बीजेपी के भीतर से भी समय-समय पर मंदिर निर्माण की आवाज उठती रहती है। मंदिर से लेकर तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 24 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक भी करने जा रहा है, जो इस दिशा में 'मील का पत्थर' साबित हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, योगी सरकार के तमाम मंत्रियों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें हिस्सा लेंगे। हाल ही में नागपुर में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर पर ताजा बयान के बाद इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। मोहन भागवत के अलावा संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल सहित कई अन्य प्रमुख लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में योगी सरकार के कामकाज, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में कई चेहरों के भविष्य पर भी मुहर लगेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव का रोडमैप बनाने के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी। बहरहाल, लाख टके का सवाल यही है कि क्या आम चुनाव से पूर्व मंदिर निर्माण हो पायेगा ? या यह एक बार फिर चुनावी शिगूफा साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से राम मंदिर के नाम पर सियासत का आरोप लगता रहा है। खासकर, जब से केन्द्र में मोदी और यूपी में योगी का राज आया है तब से यह हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी जब भी किसी मंच पर मंदिर निर्माण की वकालत करती तो विपक्ष बीजेपी पर तंज कसने लगता है, 'मंदिर वहीं बनायेंगे, पर तारीख नहीं बतायेंगे।' मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण विपक्ष के हमले से बीजेपी तिलमिला कर रह जाती है। यह सिलसिला कई वर्षों से अनवरत जारी था। मंदिर निर्माण ऐसा मुददा था, जिसकी मुखालफत करके मुलायम और लालू यादव जैसे नेता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने बीजेपी की राम मंदिर निर्माण की सियासत के खिलाफ लामबंदी करके मुस्लिम वोटों की खूब लामबंदी की। बीजेपी को साम्प्रदायिक पार्टी करार दे दिया गया। मुसलामनों को डराया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जायेगी तो उनके लिये देश में रहना मुश्किल हो जायेगा। मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ही पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि प्राकतिक सम्पदा पर पहला हक मुसलमानों का है। मुस्लिम तुष्टिकरण का यह सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा। ऊंच-नीच के नाम पर हिन्दुओं को आपस में लड़ाया गया। यह सिलसिला 2014 में तब कमजोर पड़ा जब मोदी ने विरोधियों की तुष्टिकरण की सियासत के खिलाफ हिन्दुत्व को धार देकर शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। शर्मनाक हार के लिये के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिये एंटोनी कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस को हिन्दू विरोधी छवि के कारण नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को एंटोनी कमेटी की बात समझ में नहीं आई। उधर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे नेताओं का मुस्लिम वोटों की सियासत से मोहभंग नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी हिन्दुत्व के सहारे एक के बाद एक राज्य में सत्तारूढ़ होती जा रही थी। वैसे, हकीकत यह भी है कि राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी फैसला आने की उम्मीद किसी को नहीं है। अगर मोदी सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दे तो बीजेपी को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के साथ-साथ इसी वर्ष के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। योगी सरकार मंदिर निर्माण के लिये प्रस्ताव केन्द्र को भेज सकती है, जिसको आधार बनाकर मोदी सरकार इसे लोकसभा में आसानी से पारित करा लेगी, तो राज्यसभा में भी शायद ही कोई खास अड़चन आए। राजनैतिक नुकसान के डर से कांग्रेस शायद मंदिर निर्माण के लिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, जैसा राग नहीं अलाप सकेगी। इसके अलावा विपक्ष के कुछ हिन्दू सांसद भी मंदिर निर्माण के पक्ष में आ सकते हैं। यह बात इस लिये पुख्ता तौर पर कही जा सकती है क्योंकि अब गैर बीजेपी दल ऐसे किसी मुद्दे को हवा नहीं देते हैं जिससे हिन्दू समाज नाराज हो जाये। इसीलिये तो जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया तो कहीं भी विरोध के स्वर नहीं फूटे। इससे पहले मदरसों की मनमानी पर योगी सरकार ने डंडा चलाया। मदरसों में राष्ट्रीय गान को गाना अनिवार्य किया। बूचड़खानों पर सख्ती की, लेकिन किसी भी दल ने इन फैसलों के खिलाफ योगी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत करने वालों को डर सता रहा था कि कहीं हिन्दू वोटर नाराज न हो जायें।

लब्बोलुआब यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष जिस तरह से लामबंदी कर रहा है। सरकार के हर फैसले पर उंगली उठाई जा रही है। जनआक्रोश को भड़काया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को हवा-पानी देकर मोदी सरकार को पूरी तरफ असफल करार दिया जा रहा है। भगोड़े उद्योगपतियों- विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की आड़ लेकर केन्द्र सरकार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। लड़ाकू विमान राफेल की डील में 'खेल' की बात प्रचारित की जा रही है। उसके चलते मोदी की राह आसान नहीं लगती है। ऐसे में हिन्दुत्व का उभार बीजेपी की नैया पार लगाने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए सपा-बसपा के गठबंधन में कांग्रेस व रालोद के शामिल होने पर भी सहमति बन गई है। महागठबंधन सभी सीटों पर भाजपा के खिलाफ साझा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। जानकारों की मानें तो सीटों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। बसपा लगभग 40 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में सपा को अपने खाते से सीटें कांग्रेस व रालोद को बांटनी पड़ सकती हैं। सपा अगर 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो उसे 10 सीटें कांग्रेस व रालोद को देनी पड़ सकती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस व रालोद बसपा-सपा की शर्तों पर गठबंधन में शामिल होने को तैयार होते हैं या कोई अलग राह चुनते हैं। सवाल यह भी है कि शिवपाल यादव का सेक्युलर मोर्चा, डॉ. अयूब की पीस पार्टी, कौमी एकता दल जैसे छोटे दलों जिनकी कुछ विशेष इलाके में अच्छी खासी पैठ है, वह किस करवट बैठेंगे।

राफेल मामले में भ्रष्टाचार का और कौन-सा सुबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट को

सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल-सौदे पर उंगली उठा दी है। उसने सरकार से यह पूछा है कि वह उसे सिर्फ यह बताए कि इन राफेल विमानों की खरीद का फैसला कैसे किया गया है ? अदालत को इससे मतलब नहीं कि इन विमानों को तिगुना पैसा देकर क्यों खरीदा गया है और तकनीकी दृष्टि से ये कितने शक्तिशाली हैं ? अदालत का यह तर्क समझने में मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। 500 करोड़ रु. का विमान 1600 करोड़ में खरीदा जाए और आपको इस लूट-पाट की चिंता नहीं है ? कमाल है ? यह पैसा किसका है ? इस देश की गरीब जनता का है। किसी नेता या जनरल के बाप का नहीं है। यदि किसी जज का नौकर 100 रु. किलो के अनार के 300 रु. दे आए तो क्या जज साहब उससे पूछेंगे भी नहीं ?

माना कि राफेल विमान, अनार नहीं है। यदि उसकी कुछ खचीर्ली और अतिरिक्त सामरिक विशेषताओं को सरकार गोपनीय रखना चाहती है तो जरूर रखे लेकिन उसे मोटे तौर पर जनता को यह बताना चाहिए कि वह इन 36 विमानों के 60 हजार करोड़ रु. क्यों दे रही है ? यदि इसे वह छुपाएगी तो यह बोफोर्स से हजार गुना बड़ा भ्रष्टाचार बनकर उसके गले की चट्टान बन जाएगा। वह सिर्फ 60 करोड़ का था। यह 60 हजार करोड़ का है। राजीव गांधी की चुप्पी उस भोले प्रधानमंत्री को ले डूबी लेकिन चतुर-चालाक मोदी की चुप्पी ने बेजान नेताओं की आवाज में जान डाल दी है। बोफोर्स के बंद मामले को फिर से अदालत में ले जाने और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस वक्त पेरिस भेजने से इस सौदे में भ्रष्टाचार का शक बढ़ गया है। फ्रांसीसी अखबारों में पहले राष्ट्रपति ओलांद और अब दासाल्ट कंपनी के अधिकारियों के बयान छपे हैं, जो कहते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी को बिचौलिया बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार का ही था। अदालत को अब और कौन-सा प्रमाण चाहिए ? क्या प्रधानमंत्री मोदी या तत्कालीन रक्षा मंत्री पर्रिकर ने अंबानी का नाम लिखकर दासाल्ट कंपनी को दिया होगा ? ऐसे घपले कलम से नहीं होते, मुंह से होते हैं। अदालत उनका मुंह कैसे पकड़ेगी ? अदालत शायद सरकार का कान पकड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी सीधे नहीं, अपने हाथ को घुमा-फिराकर याने यदि अनिल अंबानी की दलाली की बात पकड़ा गई तो फिर यह सिद्ध करने की शायद जरूरत नहीं रहेगी कि 500 करोड़ के 1600 करोड़ क्यों हुए ? लोग सारी बात अपने आप समझ जाएंगे।

IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था दौड़ता हुआ हाथी

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने केंद्र की एनडीए सरकार की तरफ से पिछले चार वर्षों में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है, लेकिन यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है। आईएमएफ की रिपोर्ट में चालू साल में भारत की आर्थिक विकास दर 7.3 फीसद रहने और इसके बाद के साल में 7.5 फीसद होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही सरकारी बैंकों की मौजूदा स्थिति और जटिल भूमि व श्रम सुधारों को तेज आर्थिक विकास दर की राह की बड़ी दिक्कतों के तौर पर गिनाया गया है। जीएसटी को एक बड़े टैक्स सुधार का दर्जा देते हुए आईएमएफ का कहना है कि इसका व्यापक फायदा तभी होगा जब सिंगल दर की व्यवस्था लागू होगी। आईएमएफ की भारत पर बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट हाल के दिनों में किसी अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान की तरफ से जारी की गई सबसे बड़ी रिपोर्ट है।

INTERNATIONAL MONETARY FUND

एनपीए सरकार के लिए बड़ी चिंता

इसे तैयार करने के लिए आईएमएफ के दल ने कई बार भारत का दौरा किया और यहां सरकार, वित्त मंत्रालय व अन्य एजेंसियों से विचार विमर्श किया है। इसमें फंसे कर्जे (एनपीए) की समस्या को बेहद चिंताजनक बताया गया है। एनपीए की समस्या के खात्मे के लिए सरकार की तरफ से दिवालिया कानून बनाने, आरबीआई की तरफ से नया दिशा निर्देश लाने जैसे कदमों को सही दिशा में उठाया गया कदम करार दिया गया है।

अलबर्ट डेविट केमिकल्स के मजदूर धरने पर

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

गाजियाबाद। अलबर्ट डेविट केमिकल्स मजदूर यूनियन गाजियाबाद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को दिया। यूनियन के मंत्री ज्ञानेन्द्र मिश्र ने बताया कि कंपनी के सीईओ टीएस परमार्थ द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। मामले को यूनियन ने गंभीरता से लेते हुए जोर शोर से उठाते हुए सीएम के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीईओं से वार्ता करने की मांग की थी। जिस पर संदर्भ लेते हुए चीफ सेकेट्ररी ने सीईओं को यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता का आदेश दिया।

आरोप है कि सीईओ ने वार्ता की और समाप्त होने के फोरन बाद तीन श्रमिको को निकाल दिया। तब से वह धरना प्रदर्शन कर रहे है मगर कोई भी उनकी सुनने वाला नही है।

जानें, जॉब नहीं मिलने की क्या है असली वजह, नीति आयोग ने किया खुलासा

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

देश में नौकरियों की किल्लत की सबसे बड़ी वजह श्रम कानूनों का सख्त होना नहीं है, जैसा कि इंडस्ट्री और कॉरपोरेट कंपनियां दावा करती आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय कंपनियों द्वारा उन सेक्टर में निवेश नहीं करना है, जहां अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. यह खुलासा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने किया है.

आंत्र प्रेन्योर्स मुनाफा कमाने वाले सेक्टर में करते हैं निवेश

नीति आयोग ने कहा है कि देश के आंत्र प्रेन्योर्स सिर्फ उन्हीं सेक्टरों में निवेश करते हैं, जहां से वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. वे ऐसे सेक्टर में निवेश करने से बचते हैं, जहां से अधिक संख्या में रोजगार निकल सकते हैं.

गुजरात में सबसे प्रगतिशील श्रम कानून है

31 अगस्त को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का पद छोड़ रहे पनगढ़िया ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में देश के सबसे प्रगतिशील श्रम कानून हैं,

इसके बावजूद रोजगार सृजन के मामले में वहां भी कोई खास प्रगति नहीं हो रही है.

श्रम कानूनों को उदार बना रहे हैं राज्य

2017-20 के लिए तीन सालका एक्शन एजेंडा जारी करने के अवसर पर केंद्रीय श्रमसचिव एम साथीयावथी ने भी कहा कि राज्य सरकारें लगातार श्रमकानूनों को उदार बना रही हैं, ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंडस्ट्री को सरकार से और क्या चाहिए.

क्या है एक्शन एजेंडे में

सरकार के एक्शन एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रक्षा, रेलवे और रोड के विस्तार और विकास पर तीन सालों के दौरान भारी खर्च किया जाएगा.

प्रो. जीडी अग्रवाल की मौत का जिम्मेदार कौन...

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

प्रो. जीडी अग्रवाल (स्वामी सानंद) नहीं रहे. अपने जीते जी गंगा को साफ-सुथरा होता देखने की चाह रखने वाले प्रोफेसर अग्रवाल पिछले 111 दिनों से अनशन पर थे. इस दौरान उन्होंने सरकार को कई दफे पत्र लिखा और चाहा की गंगा की सफाई के नाम पर नारेबाजी-भाषणबाजी के अलावा कुछ ठोस हो, लेकिन सरकारों का रवैया जस का तस रहा. ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर अग्रवाल पहली बार अनशन पर बैठे थे. वह पूर्ववर्ती सरकारों में भी अनशन पर बैठे थे और तब भी उनकी यही मांग थी और इस बार जब वे अनशन पर बैठे तब केंद्र में गाय और गंगा की बात करने वाली सरकार थी, ऐसे में इस मसले को और संवेदनशीलता से देखने और निपटने की जरूरत थी लेकिन हुआ क्या...! न तो गंगा में गिरने वाली गंदगी पर लगाम लग पाई है और न ही अवैध खनन रुका है. केदारनाथ की भयानक आपदा तो याद होगी आपको ! उस आपदा में हजारों जानें गई थीं. उसके बाद तमाम वैज्ञानिकों ने इस आपदा का अध्ययन किया और लगभग सभी रिपोर्ट में गंगा का जिक्र था और कहा गया कि गंगा को बचाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो ऐसी आपदाओं को रोका नहीं जा सकता. 2014 में वन और पर्यावरण मंत्रालय ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी और स्वीकार किया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से केदारनाथ आपदा ने और विकराल रूप धारण किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गंगा नदी के बेसिन में बन रहे बांधों पर रोक लगाने की जरूरत भी बताई. 2016 में इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि बांधों की वजह से गंगा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद से गंगा में कितना पानी बह चुका है यह शायद सरकार को भी याद न हो. तमाम बांध परियोजनाओं पर जोर शोर से काम चल रहा है. सिर्फ गंगा पर ही 24 बांध प्रस्तावित हैं, जिनपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है. इससे पहले भी तमाम समितियों ने नदियों के अस्तित्व से छेड़छाड़ को लेकर चेताया है लेकिन उन समितियों की रिपोर्ट पर कितना अमल हुआ और कितना नहीं इसका कोई ठीक-ठाक ब्योरा नहीं है. हाल ही में केरल में आई भयानक बाढ़ की विभीषिका आप भूले नहीं होंगे. वैज्ञानिकों ने इसे मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा करार दिया. पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गाडगिल ने कहा कि विकास की दौड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तमाम बातों का जिक्र किया था लेकिन उस पर ठोस अमल नहीं हुआ और नतीजा सबने देखा. जब यह सरकार बनी तो गंगा की सफाई और स्वच्छता को लेकर जोर शोर से बात हुई. दावे तो यहां तक किए गए कि गंगा साफ नहीं हुई तो जान दे दूंगी लेकिन वास्तव में गंगा कितनी साफ हुई यह प्रोफेसर अग्रवाल से बेहतर कौन बता सकता था! प्रोफेसर अग्रवाल नहीं रहे. वह अपने आपमें एक संस्था थे. सरकार और सिस्टम की संवेदनहीनता ने एक संस्था और ईमानदार प्रयास को निगल लिया. आज ही एक खबर छपी है. सरकार का कहना है कि गंगा और यमुना की सफाई का मिशन पूरा होने के बाद देश-दुनिया की अन्य नदियां भी मीटू का आह्वान करेंगी. प्रोफेसर अग्रवाल होते तो इस खबर को पढ़कर हंस रहे होते, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपी पीड़ा की किसे परवाह!

> ☐ तमाम बांध परियोजनाओं पर जोर शोर से काम चल रहा है . सिर्फ गंगा पर ही 24 बांध प्रस्तावित हैं, जिनपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है

फाइलें दबाकर बैठने वाले बाबुओं को नहीं मिलेगा प्रमोशन!

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब सरकारी दफ्तरों में फाइलों की मूवमेंट ट्रैक की जाएगी और काम निपटाने में तेजी या सुस्ती के आधार पर कर्मचारियों को तरक्की मिलेगी. फाइलें दबाकर बैठने वाले सरकारी बाबूओं को नहीं मिलेगा प्रमोशन! मोदी सरकार बनाएगी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम सरकारी दफ्तरों में अब फाइलें दबाकर बैठने वाले बाबुओं की खैर नहीं. किस सरकारी बाबू ने आप से जुड़ी किस फाइल को कितनी देर तक रोक कर रखा है, इसका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों के परफॉरमेंस अप्रेजल में किया जाएगा.

जल्दी काम निपटाने वाले होंगे सम्मानित

इसके लिए ई-ऑफिस से रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है जिसमें दिन, घंटे, मिनट और सेकंड तक का हिसाब होगा. इसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉरमेंस असेसमेंट रिपोर्ट में हो सकता है. अब कम समय में फाइल निपटाने वाले सम्मानित होंगे.

मोदी सरकार बना रही ट्रैकिंग सिस्टम

पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई खुदरा महंगाई, सितंबर में 3.77 प्रतिशत पर पहुंची

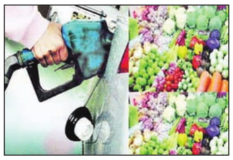

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नई दिल्ली। ईंधन और खाने-पीने की चीजों के ऊंचे दाम से खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में मामूली रूप से बढ़कर 3.77 प्रतिशत पर पहुंच गई. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. सरकारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर इससे पिछले महीने 3.69 प्रतिशत थी. यह 10 महीने का न्यूनतम स्तर था. हालांकि, सितंबर महीने में बढ़ने के बाद भी मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के दायरे में ही है. अनाज, मांस और मछली, अंडा, दूध उत्पाद जैसी श्रेणियों में खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी का रुख बना हुआ है.

हालांकि, फलों के मामले में मुद्रास्फीति सितंबर में नरम रही यानी फलों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई. कुल मिलाकर उपभोक्ता खाद्य श्रेणी में महंगाई दर बढ़कर 0.51 प्रतिशत रही जो अगस्त में 0.29 प्रतिशत थी. ईंधन और प्रकाश कैटेगरी की बात की जाए तो सितंबर महीने में इस वर्ग में मुद्रास्फीति 8.47 प्रतिशत रही.

शासनादेश के बाद शस्त्र लाइसेंस के लिए मचेगी होड़

शस्त्र साइंसेस बनाने की कतार मे नेता, व्यापारी, वकील, कारोबारी और बिल्डर

शस्त्र लाइसेंस पहले प्रक्रिया पूरी, फिर आवश्यकतानुसार बनाना संभव

- ☐ पिस्टल-रिवॉल्वर को अब देनी होगी 50 हजार की एनएससी
- ☐ जनपद में पहले ही 15,625 शस्त्र लाइसेंस धारक है
- ☐ डीएम के लिए बड़ी चुनौती

शस्त्र लाइसेंस पहले प्रक्रिया पूरी, फिर आवश्यकतानुसार बनाना संभव

शस्त्र लाइसेंस की पहले पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही आवश्यकतानुसार लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। वारिसान के ट्रांसफर के अलावा हादसों से पीड़ित लोगों के प्राथमिकता पर जांच पूरी होने के बाद जारी किए जा सकेंगे। शासनादेश को देखने के बाद ही शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिनके खिलाफ कोई मामला लंबित हो। तहसील, पुलिस व प्रशासनिक स्तर से पूरी रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे।

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

गाजियाबाद। प्रदेश सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस बनाने के लिए जारी किए जाने वाले शासनादेश के बाद अब जिले में असलाह का लाइसेंस बनवाने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों में होड़ मचनी शुरू हो गई है। इसे मात्र स्टेट्स सिंबल कहे या फिर मुसीबत में अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को शस्त्र लाइसेंस बनवा कर असलहा रखने की जरूरत। मामला कुछ भी हो लेकिन लाइसेन्स बनवाने वालों की कतार बहुत लंबी है। आदेश आने के बाद नेताओं से लेकर कारोबारी, नौकरी पेशा, बिल्डर समेत तमाम लोगों में अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए होड़ सी मच गयी हैं। गाज़ियाबाद डीएम रितु माहेश्वरी के लिए हालांकि शस्त्र लाइसेंस की चाहत वालों के लाइसेंस बनाना फिलहाल बड़ी चुनौती के समान दिख रहा हैं। जिले में पहले से ही करीब 15 हजार 625 शस्त्र लाइसेंस धारक है। आखिर प्रदेश में चार साल बाद शस्त्र लाइसेंस बनाने के लिए शासनादेश जारी किए जाने से शस्त्र लाइसेंस की चाहत रखने वालों को भले ही मंशा पूरी कर दी हो। लेकिन बता दें कि प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वर्ष-2014 में यतेंद्र बनाम प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्यादा शस्त्र लाइसेंस बनाए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अगस्त-2014 में शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी थी। चार साल के लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद निर्णय हो सका। सरकार ने अब 4 साल के बाद शस्त्र लाइसेंस बनाए जाने को लेकर शासनादेश जारी कर दिया हैं। सोमवार से शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन फार्म कलेक्ट्रेट से मिलना शुरू हो जाएंगे।

शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन जमा करने वाले आवेदकों को 200 रुपए का आवेदन फार्म मिलेगा। खास बात यह है कि आवेदकों को अब नए फार्म भरकर जमा कराने होंगे। असलहा के शौक रखने वालों को पहले के सापेक्ष जेबे ढीली करनी पड़ेगी। रिवॉल्वर-पिस्टल के लिए 50 हजार रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) खरीदनी होगी। इसमें 4000 रुपए रायफल क्लब, 2000 रुपए के स्टांप,1000 रुपए की रसीद, 500 रुपए जिला क्रीड़ा समिति, 500 रुपए रेड क्रास सोसायटी के लिए जमा कराने होंगे। वहीं रायफल-30 हजार रुपए, डबल बैरल बंदूक-20 हजार, सिंगल बैरल बंदूक-10 हजार रुपए जमा कराने होंगे। 30 हजार की एनएससी में 4000 रुपए रायफल क्लब, 1500 रुपए का स्टांप, 1000 रुपए की रसीद, 500 रुपए क्रीड़ा समिति और 500 रुपए रेड क्रास सोसायटी में जमा करानी होंगी। सिंगल बैरल बंदूक का शुल्क 10 हजार की एनएससी, 3500 रुपए रायफल क्लब,1000 रुपए की रसीद,1000 रुपए का स्टांप,250-250 रुपए जिला क्रीड़ा समिति और रेड क्रॉस सोसायटी के लिए जमा कराना होगा। लाइसेंस धारक 200 कारतूस सालभर में खरीद सकेंगे। रायफल के लिए 75 कारतूस खरीदने के बाद 80 फीसद खोखे वापिस करने होंगे।

200 रुपए का आवेदन फार्म और जमा करने होंगे नए फार्म

ईएसआइसी की रिकवरी के खिलाफ नगर निगम कोर्ट में जल्द अपील दायर की जाएगी : नगर आयुक्त

> निगम के खातों से इस तरह पैसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निगम के खातों से ईएसआईसी का ट्रांसफर किया। ये गलत है और बैंक प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
>
> -नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह

- ☐ ईएसआईसी ने निकाले नगर निगम पर 9.50 करोड़

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

गाजियाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने हिस्से की 9.50 करोड़ रुपए निकालने के बाद नगर निगम के बैंक खातों को मुक्त कर दिया। नगर निगम अब इस कार्रवाई के खिलाफ ईएसआई कोर्ट में अपील दायर करेगा। ईएसआईसी ने ई-मेल से नगर निगम अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। बतादें कि गुरूवार को ईएसआईसी ने कर्मचारियों को ईएसआई के लाभ से वंचित रखने को लेकर बकाया 9.50 करोड़ रुपए जमा न करने पर नगर निगम मुख्यालय परिसर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाते सीज कर दिए थे। इस कार्रवाई के विरोध में नगर निगम कर्मचारी संघ पदाधिकारियों ने हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए थे। नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह ने हालांकि इस कार्रवाई को गलत मानते हुए कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही थी। नगर निगम अब जल्द ही ईएसआई कोर्ट में अपील दायर करेगा। नगर निगम ने अपने और ठेकेदारों के कर्मचारियों को वर्ष-2004 से अभी तक ईएसआइ के लाभ से वंचित रखा। पत्राचार होने के बाद भी जवाब नहीं देने पर ईएसआइसी ने बीते 14 सालों की रिकवरी का आदेश जारी किया। ईएसआईसी ने अपने हिस्से की धनराशि नगर निगम के बैंक खातों से निकालने के बाद खाते मुक्त कर दिए हैं। नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि निगम के खातों से इस तरह पैसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निगम के खातों से ईएसआईसी का ट्रांसफर किया, वह गलत है और बैंक प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईएसआइसी की रिकवरी के खिलाफ कोर्ट में जल्द अपील दायर की जाएगी।

आईजीआई से ढाई गुना बड़ा होगा नोएडा एयरपोर्ट

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नोएडा। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से ढाई गुना और मुंबई के हवाई अड्डे से चार गुना बड़ा होगा। यह बातें केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि सेक्टर-14 ए बिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड का काम शुरू कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी प्रयासरत हैं। मामले में एनओसी मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्टर-94 में नोएडा हैबिटेट सेंटर के लिए प्राधिकरण ने 25 एकड़ जमीन दे दी है। नोएडा में पाक कला इंस्टीट्यूट बनकर तैयार है। वहीं, देश का पहला बॉटेनिक गार्डन में भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि नोएडा को खुले में शौच से मुक्ति की स्वघोषणा की गई है, जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। इस मामले में प्राधिकरण ने इतिहास लिखा है। उन्होंने कहा कि नोएडा के विकास के लिए बहुत कुछ हुआ। हालांकि कई बार हम चूके भी हैं। इसकी बड़ी वजह दीर्घकालिक योजनाओं का न होना है।

उधर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में 50 हजार कारें एक साथ खड़ी हो सकेंगी। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर इतने वाहनों के लिए करीब 90 हजार वर्गमीटर जगह तय की गई है। इन कारों के लिए ओपन पार्किंग बनाई जाएगी। जेवर एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों को वाहनों के लिए ओपन पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। एयरपोर्ट के पहले चरण में पार्किंग के लिए 48,491 वर्ग मीटर जमीन आरक्षित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 39,584 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की जाएगी। इसमें एक साथ 50 हजार कारें एक साथ खड़ी हो सकेंगी।

50 हजार कारें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साथ पार्क हो सकेंगी

भारत विकास परिषद गाजियाबाद द्वारा 'भारत को जानो' प्रतियोगिता का आयोजन

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

गाजियाबाद। भारत विकास परिषद, गाजियाबाद मुख्य शाखा द्वारा आज भारत को जानो प्रतियोगिता के द्वितीय चरण प्रश्न मंच का आयोजन सेठ मुकंदलाल इन्टर कालेज, गाजियाबाद पर सम्पन्न किया गया। इस प्रश्न मंच में शहर के सात विद्यालयों ने सहभागिता की। यह प्रश्न मंच कम्प्यूटर के माध्यम से पर्दे पर दिखा कर भांति किया गया, जिसकी उपस्थित छात्र-छात्राओं व नगरजनो ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर प्रथम, सेठ मुकंदलाल इन्टर कालेज द्वितीय व सुशीला इन्टर कालेज तृतीय स्थान पर रहे।

कनिष्ठ वर्ग में श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज प्रथम, सेठ मुकंदलाल इन्टर कालेज द्वितीय व सेंट पॉल एकेडमी तृतीय स्थान पर रहे। सभी प्रतिभागियों को सम्मान प्रतीक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी विजयी टीमों को भी सम्मान प्रतीक, प्रमाणपत्र व उपहार भेंट किए गए। एके जैन, विनीत गोयल, मनोज अग्रवाल व प्रवेश चंद्र गुप्ता द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया।

इस अवसर पर श्रीमती मधु पोद्दार अध्यक्षा, अनिल वशिष्ठ सचिव, प्रभाकर जेपी, श्रीमती अनिता प्रभाकर, हरीश जिन्दल, योगेश गुप्ता व श्रीमती योगेश गुप्ता, धुरेन्द्र गोयल, पीयूष मित्तल, सुरेन्द्र कंसल व परिषद के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, मां सरस्वती व विवेकानंद जी के चित्रों पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत के साथ व समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। कार्यक्रम उपरांत सुरुचि भोजन के बाद सभी विदा हुए। भवदीय, प्रवेश चंद्र गुप्ता, शाखा उपाध्यक्ष व प्रान्तीय जिला मीडिया प्रभारी व प्रान्तीय जिला संयोजक गाजियाबाद भारत को जानो व विज्ञान को जानो।

महिलाओं की अपेक्षा पुरुष कर्मचारी पहली पसंद

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर पांच में से चार कंपनियों में 10 फीसद से भी कम महिला कर्मचारियों की भागीदारी है। भारत की ज्यादातर कंपनियां महिलाओं की तुलना में पुरुष कर्मचारियों को भर्ती करना पसंद करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की मानसिकता रखने वाली कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

वैश्विक औसत में पिछड़ता भारत

भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी महज 27 फीसद है जो वैश्विक औसत के मुकाबले 23 फीसद कम है। एक तरफ तो भारत में तेजी से नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महज 26 फीसद महिला कर्मियों की भर्ती देश में महिलाओं की स्थिति पर कई सवाल खड़े करती है।

रोजगार में पिछड़ती महिलाएं

भारत में तकनीक के क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। नए अवसर सृजित हो रहे हैं लेकिन चयन में लिंगभेद की वजह से इसका फायदा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को मिल रहा है।

- ☐ 27 प्रतिशत भारत में महिला कार्यबल
- ☐ 50 प्रतिशत वैश्विक स्तर पर महिला कार्यबल
- ☐ 10 में से 1 कंपनी देती हैं महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता
- ☐ 770 सर्वे में शामिल भारतीय कंपनियां
- ☐ 3 में से 1 कंपनी देती हैं पुरुष कर्मचारियों को प्राथमिकता
- ☐ 10770 में से उन कंपनियों की संख्या जहां 50 प्रतिशत या अधिक महिला कर्मचारी हैं

टेक्सटाइल सेक्टर में महिलाओं का वर्चस्व

- ● 61 प्रतिशत चैकिंग सेक्टर में महिला कर्मचारी
- ● 61 प्रतिशत टेक्सटाइल सेक्टर में महिला कर्मचारी
- ● 10 प्रतिशत रिटेल सेक्टर की 79 फीसद कंपनियों में महिला कर्मचारी
- ● 546 वे कंपनियां जहां 10 फीसद से कम महिला कर्मचारी
- ● 172 यहां पांच फीसद महिला कर्मचारी
- ● 164 में कोई महिला कर्मचारी नहीं

सरकार का एक और तोहफा: ग्रेच्युटी पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा, ब्याज दरें बढ़ी

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद एक और तोहफा दिया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, गैर-सरकारी प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी की ब्याज दरें 7.6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी गई है. आपको बता दें कि नई दरें 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए लागू होंगी. वित्त मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (एसडीएस) 1975 के तहत जमा पर ब्याज दरों में इस संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है. इससे किसकों फायदा होगा- एसडीएस की ब्याज दरों में बढ़ोतरी गैर-सरकारी पीएफ, पेंशन और ग्रैच्युटी फंडों में निश्चित रूप से अतिरिक्त मुनाफा (रिटर्न) प्राप्त करने में मदद करेगी. इन फंडों में निवेश करने वाले कर्मचारी या लाभार्थियों को लंबी अवधि में इसका फायदा मिलेगा. लेकिन, इन्हें सरकार की ओर से तय निवेश के दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है. इसका मतलब साफ है कि की अब नौकरी करने वालों को ग्रेच्युटी पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा.

> ● सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, गैर-सरकारी प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी की ब्याज दरें 7.6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी गई है.

एसडीएसी क्या होता है- केंद्र सरकार ने विशेष जमा स्कीमों यानी एसडीएस को 1 जुलाई 1975 में शुरू किया था. इस योजना का उद्देश्य गैर-सरकारी पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सरप्लस फंड और कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि से बेहतर रिटर्न प्रदान करना था. जब ये संस्थान एसडीएस में धन जमा करते हैं, तो सरकार इसमें लगाई गई रकम पर ब्याज का भुगतान करती है.

बढ़ गई ब्याज दरें- 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए ब्याज दर 7.6 फीसदी थी. जबकि जून और सितंबर तिमाहियों में इन्हें 7.6 फीसदी पर यथावत रखा गया था. सरकार ने अब दरें बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी है.

घरेलू कपड़ा उद्योग में सुधार के संकेत : सीआईटीआई

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई) के अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि देश के कपड़ा उद्योग का बुरा दौर समाप्त हो गया है और अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं. संजय जैन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का वस्त्र एवं परिधान निर्यात सात फीसदी सालाना दर से बढ़ सकता है.

उन्होंने बताया कि बीते महीने जुलाई में देश का कपड़ा निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11 फीसदी बढ़ा है और कपड़े के सभी मदों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई. संजय जैन ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उद्योग को सहारा मिला है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान के विभिन्न मदों पर आयात कर बढ़ा कर घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन दिया है और इससे आने वाले दिनों में कपड़े का आयात घटेगा जिससे घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी.

भारत ने जुलाई में 6,284 करोड़ रुपये का कॉटन यार्न, फेब्रिक, मेडअप और हैंडलूम उत्पादों का निर्यात किया जोकि पिछले साल के मुकाबले 23 फीसदी ज्यादा है. टेक्सटाइल निर्यात 10,879 करोड़ रुपये रहा, जोकि पिछले साल के मुकाबले 15 फीसदी अधिक है. कॉरपेट निर्यात 774 करोड़ रुपये का हुआ जोकि पिछले साल के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा है. अपेरल निर्यात में पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई में छह फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

रूपया संभालने को NRI की मदद लेगी सरकार

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये की बिगड़ती सेहत में सुधार लाने के लिए सरकार प्रवासी भारतीयों (NRI) की मदद लेने के बारे में सोच रही है. वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारी एनआरआई से पैसे जुटाने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं. मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों ने कहा कि इस बारे में योजना का एलान इस महीने के अंत तक हो सकता है. उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. सरकार रुपये को सहारा देना चाहती है. इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले यह करीब 14 फीसदी गिर चुका है. यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा हो गई है.

भारत का व्यापार घाटा बढ़ने से रुपये पर दबाव और बढ़ जाएगा. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से पहले से ही रुपये पर दबाव है. सरकार रुपये को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है. पहले भी सरकार रुपये को ज्यादा गिरने से बचाने के लिए एनआरआई की मदद ले चुकी है. सरकार विदेश में बॉन्ड बेचा था. 2013 में आरबीआई ने फॉरन करेंसी नॉन-रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट प्लान लॉन्च किया था. इसका मकसद रुपये को मजबूती देना था. विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से 11 अरब डॉलर निकाल चुके हैं. उन्होंने इसके लिए शेयर और बॉन्ड बाजार में जमकर बिकवाली की है.

इससे रुपये पर दबाव बढ़ा है. माना जा रहा है कि भारत के लिए बढ़ते चालू खाता घाटे से निपटना मुश्किल हो सकता है. सरकार कई चीजों पर आयात शुल्क लगाने या बढ़ाने का फैसला ले चुकी है. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कंपनियों को विदेश में कर्ज जुटाने की भी इजाजत दी है. इसके बावजूद रुपये की कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भी चालू खाते का घाटा बढ़ने का डर है. इसके इस वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 75 अरब डॉलर तक पहुंच जाने के आसार हैं. यह सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 फीसदी के बराबर है. 2013 के बाद से यह सबसे ज्यादा चालू खाता घाटा होगा. हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है. ब्रेड क्रूड 86 डॉलर तक चढ़ने के बाद 81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है.

महिलाओं के प्रति साजिद का रवैया हमेशा असभ्य रहा

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

अभिनेत्री बिपाशा बसु ने शुक्रवार को फिल्मकार साजिद पर लगे आरोपों पर कहा कि वह खुश हैं कि महिलाओं ने उनके (साजिद) साथ हुए अपने अनुभवों को साझा किया। अदाकारा का कहना है कि फिल्म सेट पर महिला कलाकारों और अन्य महिला सदस्यों के साथ उनका रवैया हमेशा असभ्य रहा है। साजिद पर अदाकारा सलोनी चोपड़ा और एक पत्रकार ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वर्ष 2014 में फिल्म 'हमशकल्स' में साजिद के साथ काम कर चुकी अदाकारा ने कहा कि हालांकि निर्देशक ने उनके साथ कभी बदसलूकी नहीं की लेकिन उनका महिलाओं के प्रति रवैया हमेशा असभ्य था। बिपाशा ने ट्विटर पर एक बयान में कहा, ह्यमैं खुश हूं कि महिलाएं इन पुरुषों के अत्याचारों के खिलाफ बोल रही हैं..लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ...यह उनका महिलाओं के प्रति सामान्य व्यवहार था जो मुझे परेशान करता था, वह खुले तौर पर अश्लील मजाक करते थे और लड़कियों के प्रति उनका रवैया भी असभ्य था। उन्होंने लिखा कि उन्हें कहा गया था कि वह उन्हें कुछ ना कहें तो उन्होंने अपना काम पूरा होने के बाद निमार्ताओं को स्पष्ट कर दिया कि वह आगे कभी उनके (साजिद के) साथ कोई काम नहीं करेंगी। बिपाशा ने एक अन्य ट्वीट में भारत में 'मी टू' अभियान शुरू करने के लिए तनुश्री दत्ता की सराहना भी की। उन्होंने लिखा, 'तनुश्री दत्ता मुबारक हो...क्योंकि उनकी वजह से कई और महिलाओं को उन पुरुषों के खिलाफ बोलने की हिम्मत मिली जो महिलाओं का फायदा उठाते हैं...अपने रूतबे, ताकत और पहुंच के जरिए...।'

मीटू पर कृति सेनन ने उठाए सवाल

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने लोगों से यौन शोषण के खिलाफ 'मीटू' अभियान को जिम्मेदारी के साथ संभालने और अपनी गुमनामी के कारण अभियान को कमजोर नहीं करने का आग्रह किया। कृति का मानना है कि किसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने से पहले पुरुष और महिला को अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। 'बरेली की बर्फी' की एक्ट्रेस ने ट्विटर पर लिखा, 'क्या होगा जब किसी के खिलाफ एक 'गुमनाम लड़की' की 'मी टू' कहानी सामने आएगी? क्या हम उस पर आसानी से विश्वास कर लेंगे और वह भी बिना जाने कि वह लड़की कौन है या वास्तव में है भी या नहीं? किसी निष्कर्ष पर कोई कैसे पहुंचेगा? क्या यह सही है कि पीड़िता के नाम के बिना ही आई मी टू कहानी के आरोपी को 'दोषी' मान लिया जाए? क्या मीडिया को ऐसी कहानियों को दिखाना चाहिए?' कृति के मुताबिक, बिना पहचान की कहानी किसी का नाम और करियर दोनों खराब कर सकती है। इसलिए उन्होंने सभी से 'मी टू' अभियान को जिम्मेदारी के साथ संभालने और इसके लिए वैधानिक तरीका तलाशने को कहा है। 28 साल की एक्ट्रेस ने कहा, 'वह लोग जो अपनी मी टू कहानियां साझा करना चाहते हैं, उन सभी महिलाओं और पुरुषों को अपने नामों व चेहरों के साथ खुले में आना चाहिए. या फिर मुकदमा और कानूनी मामला दाखिल करना चाहिए ताकि मामले की जांच हो सके और मी टू अभियान न कमजोर हो सके और न इसका दुरुपयोग हो सके। कृति ने उन लड़कियों की सराहना की, जिन्होंने लोगों के सामने अपनी उत्पीड़न की कहानियों के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि मी टू अभियान लोगों में कुछ भी गलत करने से पहले डर लाएगा।

यह क्या... और बढ़ गया भ्रष्टाचार...?

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

सनसनीखेज खबर है कि इस साल देश में भ्रष्टाचार और बढ़ गया. पिछले साल तक 100 में 45 भारतीय नागरिकों को घूस देकर अपना काम करवाना पड़ता था. इस साल 56 फीसदी नागरिकों को घूस देनी पड़ी. यह बात विश्वप्रसिद्ध संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) और लोकल सर्किल्स के सर्वेक्षण से निकलकर आई है. TI पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की नापतोल का काम करती है. कुछ महीनों बाद TIभ्रष्टाचार के मामले में वैश्विक सूचकांक जारी करेगी, जिससे पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे देशों की तुलना में हमारी और कितनी दुर्गति हो रही है. बहरहाल इस सर्वेक्षण से यह जाहिर है कि भ्रष्टाचार के आने वाले वैश्विक सूचकांक में अपने देश की हालत और खराब निकलकर आने का अंदेशा बढ़ गया है.

यह तो सिर्फ निचले भ्रष्टाचार का आकलन है...

मौजूदा सर्वेक्षण पुलिस, जमीन-जायदाद के कागज बनवाने, वाहन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाने वाले दफ़्तरों, बिजली विभाग के दफ़्तरों वगैरह में घूस देने तक सीमित दिखाई दे रहा है. इसमें घटतौली, मिलावट, बैंकों में घूस, जालसाजी जैसे भ्रष्टाचारों को देखा ही नहीं जा सका है, और न ही बैंकों से कर्ज. और निर्माण कार्यो के ठेके या दूसरे बड़े लाइसेंस पाने के लिए होने वाले भ्रष्टाचार को जाना जा सका. बैंकों में हजारों करोड़ की जालसाजी और सरकारी खरीद में हुए घपले-घोटाले भी इस सर्वेक्षण से काफी दूर हैं. फिर भी यह सर्वेक्षण भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिक की व्यथा कथा बताने के लिए पर्याप्त है. और यह बताने के लिए भी पर्याप्त है कि उम्मीद तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बंधाई गई थी, लेकिन यह तो और बढ़ गया. भ्रष्टाचार एक साल के अंतराल में 45 फीसदी से बढ़कर 56 फीसदी पहुंच गया. यानी भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय पिछले साल की तुलना में 25 फीसदी और बढ़ गया. पिछले दो साल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भी अपने देश की हालत ठीक नहीं पाई गई थी।

असर उपायों का...

एक सामान्य अनुभव है कि घूस देने के लिए भी आमतौर पर एक अदद दलाल की जरूरत पड़ती है. जब से भ्रष्टाचार मिटाने के दावे हुए, उसे रोकने के उपायों के ऐलानों की भी झड़ी लगी. दफ़्तरों में CCTV कैमरे लगाने के दावे हुए, कंप्यूटर से काम का दावा हुआ. इस मामले में TI के इस सर्वेक्षण में एक और भी ज्यादा सनसनीखेज तथ्य सामने आया. वह यह कि उन ज्यादातर दफ़्तरों में या तो कैमरे और कंप्यूटर लग नहीं पाए या वहां ये उपकरण खराब पड़े मिलते हैं.

भ्रष्टाचार रोकने के प्रचार का आलम...

जहां तक भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी प्रचार का सवाल है, तो इसी सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले साल 51 फीसदी लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया. इस साल भी लगभग उतने ही यानी 48 फीसदी लोगों का कहना है कि कोई सरकारी उपाय नहीं हुआ. जो थोड़े-बहुत लोग यह मानते हैं कि उपाय तो किए गए, उनके बारे में रिपोर्ट में यह है कि पिछले साल 27 फीसदी लोग मानते थे कि उपाय नाकाम हैं, लेकिन इस साल ऐसा मानने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया. इस साल 35 फीसदी लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के सरकारी उपाय नाकाम हैं.

आखिर भ्रष्टाचार का पीड़ित कौन है...

यह अपराधशास्त्रीय सवाल है. विशेषज्ञों के विमर्श में यह सवाल खूब उठता है. विशेषज्ञ समझ यह है कि घूस देने वाला भी आमतौर पर लाभार्थी ही है. जो घूस नहीं दे पाता या जिसे घूस देने का मौका नहीं मिलता, वही ज्यादा पीड़ित है. दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार की परिघटना में इस वंचित वर्ग की पहचान और उसकी सुनवाई कहां है...? अभी अपने पास इस सिलसिले में अपराधशास्त्रीय शोध अध्ययन वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक आधी-अधूरी शोध परिकल्पना जरूर है कि यह वंचित यानी गैर-भ्रष्ट नागरिक या तो गांव में रहता है या शहरों में रोजनदारी पर मजदूरी कर ज़िन्दगी गुजार रहा है. हो सकता है कि भ्रष्टाचार सर्वेक्षण के लिए नमूने में गांव वालों और रोजनदारी वाले मजदूरों की संख्या कम रही हो.

दार्शनिक पहलू...

हैरत है कि भ्रष्टाचार सर्वेक्षण की रिपोर्ट को मीडिया में कोई अहमियत नहीं मिली. आजाद भारत के मीडिया इतिहास में यह नई घटना है. हो सकता है कि यह माना जाने लगा हो कि भ्रष्टाचार सामान्य बात है, लेकिन भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा भी है. अपनी मौजूदा सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर बाकायदा मुहिम चलाकर सत्ता तक पहुंची थी (भ्रष्टाचार में भारत की स्थिति जस की तस : क्यों नहीं हुआ सुधार...?), सो, इस तरह भ्रष्टाचार की किसी भी बात को मीडिया से यूं ही नहीं उड़ाया जा सकता. वैसे भी भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा से ही यही ज्ञान दिया जाता रहा है कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ऊपर से नीचे बहता है, और इसीलिए सदियों से माना जाता रहा है कि भ्रष्टाचार कुशासन या शासनविहीनता की उपज होती है. और अगर देश के आधे से ज्यादा लोगों को घूस देकर अपने काम करवाने पड़ रहे हों, तो बात शासन-प्रशासन तक पहुंचेगी ही.

IOC शुरू करेगी CNG और PNG बिजनेस, आपको भी मिलेगा लाखों की कमाई का मौका

उद्योग विहार (अक्टूबर-2018)

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की तरह अब देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्डउ भी सीएनजी और पीएनजी के रिटेलिंग कारोबार में उतर गई है. ऐसे में आपके पास भी मोटी कमाई का मौका आ रहा है.

आइए जानें क्या है पूरा मामला

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की तरह अब देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC भी सीएनजी और पीएनजी के रिटेलिंग कारोबार में उतर गई है. आईओसी सिटी गैस प्रोजेक्ट में 5 हजार 463 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी को बोर्ड से इस पूंजी को निवेश करने के लिए मंजूरी मिल गई है. कंपनी को हाल में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस मिले है. एक्सपर्ट्स की मानें तो IGL की तरह ही IOC भी सीएनजी स्टेशन के लिए डीलर-फ्रेंचाएजी मॉडल को अपना सकती है. अगर ऐसा होता है तो इनकी शर्तें भी काफी हद एक जैसी हो सकती है. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ. आइए जानें IGL किस तरह से लाइसेंस देती है.

सीएनजी स्टेशन देने के लिए कंपनी ने बदला नियम- आईजीएल पहले सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन की स्थापना केवल फ्रेंचाएजी मॉडल पर करती थी, जहां जमीन के साथ आउटलेट कंपनी के स्वामित्व में होता था और डीलर की नियुक्ति इसे चलाने के लिए की जाती थी. लेकिन अब कंपनी उस डीलर को फ्रेंचाएजी दे रही है, जिसके पास अपनी जमीन है.

इंडियनऑयल
IndianOil

आवेदन करना चाहते हैं तो आपके नाम पर जमीन होना जरूरी- सीएनजी पंप का मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास जमीन होना जरूरी है. हल्के वाहन के लिए 700 वर्गमीटर की जमीन होनी चाहिए, जिसमें आगे की ओर 25 मीटर होना चाहिए. इसी तरह भारी कमर्शियल वाहनों के लिए सीएनजी पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास 1500-1600 वर्गमीटर का प्लॉट होना चाहिए, जिसमें आगे की ओर 50-60 मीटर होना जरूरी है. अगर आपका प्लॉट हाईवे और भीड़-भाड़ इलाकों में है तो कंपनियां सीएनजी पंप आवंटित करने में तरजीह देगी. हालांकि लीज पर जमीन लेकर भी सीएनजी पंप का मालिक बनने का विकल्प है.

पंप खोलने के लिए बैंक देती है लोन- सीएनजी पंप खोलने में जमीन की लागत हटा दें तो इक्वीपमेंट, इम्प्लाई कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लाइसेंस फीस मिलाकर करीब एक करोड़ रुपए खर्च होते हैं. इसके लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं. सभी कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार स्टेशन पंप के लिए टेंडर निकालती है, जिसमें लोकेशन सहित दूसरी रिक्वॉयरमेंट दी जाती है. इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते है. टेंडर के लिए इन कंपनियों की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901/4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह